अनुदान संख्या 34 - निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)
GRANT No. 34 - DEPARTMENT OF INVESTMENT AND PUBLIC ASSET MANAGEMENT (DIPAM)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	48,27,00			
			68,96,00	44,82,17	-24,13,83
पूरक	Supplementary	20,69,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				24,08,81
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1,47,00			
			1,52,00	79,06	-72,94
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				72,86

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹2413.83 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹2069.00 लाख की पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 35 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹2413.83 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹2069.00 lakhs obtained in December, 2024 and constituted 35 percent of the total sanctioned provision.

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	4827.00			
पू.	S.	2069.00	4487.19	4482.17	- 5.02
पु.	R.	-2408.81			

(I) "सचिवालय – निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग" के अंतर्गत ₹4827.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2069.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹6896.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹2413.83 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने और कम व्यावसायिक शुल्क के कारण हुई।

(I) Under "Secretariat - Department of Investment and Public Asset Management" - the original provision of ₹4827.00 lakhs was augmented to ₹6896.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2069.00 lakhs. However, there was a saving of ₹2413.83 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and less professional fees.